

भारत मे बेरोजगारों का मेला

Dr. Rakshit M. Bagde

Assistant Professor, Dept of Economics, RTM Nagpur University,

Nagpur Maharashtra 440010 rakshitbagde@gmail.com

प्रस्तावना -

प्रत्येक देश मे बेरोजगारी का होना एक सामान्य बात है, भले ही वह कीतनी भी विकसीत अर्थव्यवस्था हो। परंतु असामान्य तरीके से और निरंतर बेरोजगारी का बढ़ना अर्थव्यवस्था और देश के आर्थिक विकास के लिये हानिकारक होता है। बेरोजगारी की समस्या व्यक्ती और समाज में हिन भावना निर्माण करती है. इससे समाज की प्रगती बाधीत होती है। आज विश्व के प्रत्येक देश को बेरोजगारी का सामना करना पड राहा है। प्रस्तुत शोध निबंध मे भारत मे बढ़ती हुयी बेरोजगारी तथा उसका विकास पस प्रभाव का अध्ययण किया गया है।

शब्द कुंजी - भारत, बेरोजगारी, विकास

भारत एक ऐसा देश है, जो अपनी स्वतंत्रता से ही बेरोजगारी से जुझ रहा है। एक व्यक्ती जो कार्य करने के लिए योग्य तथा तत्पर है लेकिन वह कार्यविहीन है,को बेरोजगारी के रूप मे परिभाषित कर सकते है। भारतीय परिपेक्ष मे बेरोजगारी देश मे भयंकर गरिबी को जन्म दे रही है। भारतीय बेरोजगारी एक सामाजिक-आर्थिक समस्या बन रही है जो आधुनिक काल मे अपना उग्र रूप धारण किए हुये है।

बेरोजगारी के लिए अनेक कारण जिम्मेदार बताये जा सकते है। भारत मे हो रहा अंधाधुंद मशिनीकरण, बढ़ती हुयी जनसंख्या, गिरता हुवा विकास दर, अशिक्षा तथा जातीव्यवस्था इनमे प्रमुख कारण बताये जा सकते है.।

परिभाषा -

बेरोजगारी उन विवादास्पत शब्दो मे से एक है, जिसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति करते है, तथा जिसके सामान्य अर्थ से लगभग सभी व्यक्ति परिचीत है।

प्रो. पीगु के अनुसार- “बेरोजगार केवल वह व्यक्ति होता है, जो काम करने की ईच्छा रखता है, परंतु काम न मिलने के कारण बेरोजगार है।”

दांडेकर एव रथ के अनुसार- “यदि व्यक्ति अपनी आय से जिवीत रहने के लिए आवश्यक कैलरी उर्जा तथा प्रोटीन नही जुटा पाता, तो वह बेरोजगार है।”

संशोधन साहित्य का अवलोकन -

Sen A.K. (1973) – “Employment, Technology and Development” इस कीताब मे संस्थानो, प्रोद्योगिकी और रोजगार के बिच आंतर संबंधो पर ध्यान आकर्षित कीया है। उत्पादन के तरीके, स्वामीत्व के पैटर्न और रोजगार व्यवस्था का अध्ययन इसके प्रमुख बिंदु है।

Abraham vinoj (2017) – “Stagnant employment Growth” इस संशोधन लेख के माध्यम से भारतीय श्रम ब्युरो के आंकड़ों के आधार पर भारतीय बेरोजगारी में आ रही बढ़ोत्तरी का विश्लेषण किया गया है।

बेरोजगारी बढ़ने के कारण -

1) विकास की धिमी गती -

भारतीय अर्थव्यवस्था तीन स्तरों में बटी हुई है। इन तीनों क्षेत्रों का विकास ही अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के विकास की गति को सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर मापा जाता है।

वर्ष	स.घ.उ. %
2017	6.68
2016	7.11
2015	8.16
2014	7.14

यहां वर्ष 2017 में GDP में आयी कमी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है।

2) जनसंख्या वृद्धि -

भारत में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या बेरोजगारी में इजाफा कर रही है। भारत में प्रतिवर्ष 1.30 करोड़ की दर से बढ़कर आज 1,36,09,19,900 करोड़ हो चुकी है। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर निर्माण करने में सरकार असमर्थ दिखायी दे रही है।

3) तांत्रिक प्रगति -

भारत में औद्योगिक स्तर पर हो रहा आधुनिकीकरण तथा नविन उपकरणों का बढ़ता हुआ उपयोग बढ़ती हुई श्रमशक्ति को काम से बेदखल कर रही है।

4) शिक्षा प्रणाली -

भारत में आज भी विश्वविद्यालय स्तर तक पारंपारिक शिक्षा प्रणाली मौजूद है। जिसकी वजह से रोजगारपुरक शिक्षा के अवसर निर्माण न होना बेरोजगारी में बढ़ावा दे रहे हैं।

5) लघु उद्योगों का पतन -

वैश्वीकरण की नीति का देश में बड़े पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया। जिसमें बड़े उद्योगों के विकास की ओर ध्यान दिया गया। जिस कारण लघु और छोटे उद्योगों का पतन हो गया, जो कि देश में रोजगार निर्माण करने में ज्यादा सक्षम थे।

6) दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन -

सन 1951 से लेकर आज तक देश ने 13 पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी की हैं। इन सभी योजनाओं में आर्थिक नियोजन का अभाव देखा गया है। जिसका सिधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। नियोजनकारों ने रोजगार बढ़ाने के अवसरों पर ध्यान नहीं देने से बेरोजगारी में वृद्धि देखी जा सकती है।

बेरोजगारी की विद्यमान अवस्था -

हमारी अर्थव्यवस्था तीन क्षेत्रों में बटी हुई है। जिसमें रोजगार निर्माण में आज भी प्राथमिक क्षेत्र अपना स्थान बनाये हुये है।

1) कृषि -

भारत में आज भी रोजगार देने में कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण बनी हुई है। हालांकि GDP में इस क्षेत्र का हिस्सा सिर्फ 17% है।

वर्ष	रोजगार प्रतिशत में
1991	63.58
2000	59.65
2005	56.00
2010	51.51
2012	47.04
2014	47.000
2016	43.44
2017	42.73

स्रोत- आंतराष्ट्रीय श्रम संघटन, सितंबर 2018

उपरोक्त सारणी दर्शाती है की, रोजगार साल दरसाल कम होता जा रहा है। जहाँ 1991 में 64 लोगों को रोजगार देने की क्षमता थी वह कम होकर सन 2018 तक 43 हो गयी है।

2) उद्योग क्षेत्र -

सन 1991 से लघु उद्योगों का लगातार बंद होना तथा बड़े उद्योगों से मजदूरों का काम से बेदखल करने का सिलसिला अभी तक बरकरार है। निर्माण क्षेत्र में लगभग 4.2 लाख रोजगार कम होता हुआ दिखायी देता है। AIMO के आंकड़े बताते हैं की, देश में नोटबंदी के बाद के दो महिनो में व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पंजीकृत नौकरियों के नुकसान की दर लगभग 55% थी। जनवरी और मार्च 2017 के बीच यह 30-40% गिर गया। जुलाई-अक्टूबर 2017 तक नौकरी सृजन का दर 5%-10% गिर गया था। AIMO के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. ई. के. रघुनाथन ने कहा था “की पिछले एक साल में नये अतिरिक्त परियोजनाएँ, निवेश, स्टार्टअप की कोई महत्वपूर्ण दर नहीं रही है।”

3) सेवा क्षेत्र -

सेवा क्षेत्र में भारत की जनसंख्या का 28.6% हिस्सा कार्यरत है। भारत में 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी तथा 1 जुलाई 2017 की GST का सिधा प्रभाव सेवा क्षेत्र पर पडा है। ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस के एक सर्वेक्षण पाया गया की, भारत के 63 मिलीयन छोटे व्यवसायों में से पाचवाँ हिस्सा याने अर्थव्यवस्था में 32% का योगदान और 111 मिलीयन लोगों को रोजगार देता है। जहा GST लागु होने से इसमें 20% गिरावट का सामना करना पडा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, मुंबई स्थित कंसल्टेंसी के अनुमानों के मुताबीक “साल 2017 में करीब पाच मिलीयन मजदूरोंको GST के कारण नौकरी से हाथ धोना पडा है।” अखील

भारतीय व्यापार संघ के राष्ट्रिय सचिव ने कहा की, “GST की अनुपालन और नगदी प्रवाह की समस्याओं के कारण लगभग 2,30,000 छोटे व्यवसाय बंद हो गये है।”

निष्कर्ष – भारत मे हुयी नोटबंदी तथा GST कहर ढा रही है। शुरूवात के सिर्फ 398 दिनों मे नोटबंदी 70 लाख लोगों को बेरोजगार कर गयी, तथा चार लाख करोड का नुकसान कर गयी। नोटबंदी के दिनों मे 183 नियमों मे बदलाव देखे गये तथा 122 लोगों को अपनी जान गवानी पडी।

वर्ष	बेरोजगारी % मे
2008	4.12
2010	3.54
2012	3.62
2014	3.41
2016	3.51
2017	3.52

स्त्रोत-Tradeconomics.com

ILO की रिपोर्ट के अनुसार देश मे 18.0 बिलियन लोग बेरोजगार है। सन 2015-16 से देश मे महिला श्रम भागीदारी गिरती जा रही है। देश मे 77% रोजगार चिंताजनक बना हुआ है। ILO के आंकडोसे पता चलता है की, इस साल वैश्विक स्तर पर 1.4 अरब लोगो के असुरक्षित रोजगार का अनुमान है। इनमे 394 मिलीयन या 1/4 से अधिक अकेले भारत का हिस्सा है। नौकरीयों पर सरकार का राष्ट्रिय नमुना सर्वेक्षण 2017-18 अभी तक जारी नहीं कीया गया है। जनवरी-अप्रैल 2017 के दौरान लगभग 1.5 मिलीयन नौकरीयों खो गयी थी। इस अवधी मे अनुमानित रोजगार कुल 406 मिलीयन की तुलना मे 406.5 मिलीयन था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार नवंबर 2018 मे भारत मे संभावित बेरोजगारी की दर 8.9% रहने कि संभावना है, जो की भारत को बेरोजगारी में विश्व में नंबर एक बना सकती है। बडे पैमाने पर बेरोजगारी का बढना भारत जैसे नौजवानो से भरे पडे देश के लीए तथा भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक खतरे की और संकेत करता है।

संदर्भ ग्रंथ सुचि -

Sen A.K. (1973) - “Employment, Technology and Development”, Oxford India Paperbacks.

Mathew E. T. (2006)-“Employment and unemployment in India : emerging tendencies during the post-reform period”, Sage Publications New Delhi

Abraham Vinoj (2017)-“Stagnant employment growth”, EPW Vol52, Issue No-38 Sep.Datta& Mahajan Ashavani (2017)-“Indian Economics”- S.Chand Publication, New Delhi.

Indianexpress.com/article 24 Dec 2018

Times of India.indiatimes.com 24 Dec 2018

www.worldmeters.info/world-population/india 19 Dec 2018

www.cmie.com 24 Dec 2018